

[1981] 1 एस. सी. आर. 884

एम. लहिया सेट्टी एंड संस लिमिटेड आदि

बनाम

द कॉफी बोर्ड, बेंगलोर

9 अक्टूबर, 1980

[न्यायमूर्ति वी. डी. तुलजापुरकर और न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक,]

नीलामी बिक्री- नीलामीकर्ता, क्या वह नीलामी आयोजित करने की अपनी शर्तें अधिरोपित करने में सक्षम है- चूककर्ता और गैर-चूककर्ता पक्षों के अधिकारों की सुपुर्दगी नहीं ली गई वस्तुओं की पुनर्विक्रय में हानि का शमन।

आंतरिक खपत के लिए व्यापार में कच्चे कॉफी के बीज जारी करने के लिए प्रतिवादी (कॉफी बोर्ड) द्वारा अपनाई गई तीन विधियों में से एक "पूल नीलामी" थी जिसमें केवल बोर्ड के साथ पंजीकृत डीलरों को भाग लेने की अनुमति थी। पूल नीलामी एक बिक्री संचालन अधिकारी (जो बोर्ड के मुख्य विपणन अधिकारी थे) द्वारा आयोजित की गई थी। बिक्री की शर्तों की शर्त 8 में कहा गया है, "बोली के संबंध में टेलीग्राफिक बोलियों या

टेलीग्राफिक निर्देशों पर विचार नहीं किया जाएगा।" शर्त 6 में कहा गया है, "विक्रेता उच्चतम या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है। वह अपने निर्णय के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है और उसका निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

दो अपीलार्थियों, जो पंजीकृत विक्रेता थे, द्वारा दी गई बोलियां पूल नीलामी को बिक्री संचालन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था, भले ही बोलियां सबसे अधिक नहीं थीं। स्टॉक की डिलीवरी लेने में उनकी विफलता पर और निर्धारित अवधि के भीतर बोली राशि का भुगतान करने के लिए, बोर्ड ने अपीलार्थियों को उचित सूचना देने के बाद दो महीने बाद एक अन्य पूल नीलामी में स्टॉक को फिर से बेच दिया। पुनः नीलामी में प्राप्त मूल्य अपीलार्थी की बोलियों की तुलना में बहुत कम होने के कारण, बोर्ड ने मुकदमों के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की।

अपीलकर्ताओं ने बोर्ड को नुकसान की भरपाई करने के लिए दायित्व को मुख्यतः इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि पक्षों के बीच कोई निष्कर्षित अनुबंध नहीं था, जिसमें अपीलकर्ताओं ने नीलामी के परिणामों की घोषणा से पहले अपनी बोलियों को रद्द करने के लिए बोर्ड को टेलीग्राम भेजे थे। एक मामले में पांच लॉट के संबंध में कोई अनुबंध समाप्त नहीं हुआ था क्योंकि खंड 6 के तहत भी बोर्ड के पास उच्च बोली प्राप्त होने पर कम बोली स्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं थी, जो उसने किया था; और

यह कि अपीलकर्ता उस नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं थे, जिसे बोर्ड ने उनके द्वारा बोली गए स्टॉक की पुनर्बिक्री से उत्पन्न होने के रूप में दावा किया था, जिसमें नुकसान का कारण बोर्ड द्वारा कीमतों को जानबूझकर कम करना था और आगे पुनः बिक्री आयोजित करने में अत्यधिक देरी करना था।

दूसरी ओर, बोर्ड ने आरोप लगाया कि शर्त 8 किसी भी बोली को टेलीग्राफिक रूप से वापस लेने या वापस लेने की अनुमति नहीं देती है और चूंकि संबंधित अधिकारी को मौखिक वापसी ठीक से नहीं की गई थी, इसलिए एक निष्कर्षित अनुबंध था; कदाचार को रोकने के लिए शर्त 6 बनाई गई थी डीलर आपस में रिंग बनाकर स्टॉक पर कब्जा कर लेते हैं स्वयं और गैरकानूनी लाभ कमाने के लिए कीमतें बढ़ा रहे हैं उपभोक्ता का नुकसान और अंततः नुकसान स्टॉक की पुनर्विक्रय में गिरावट का परिणाम था पुनर्विक्रय के समय कीमतें अवास्तविक नहीं थी।

अपीलकर्ताओं के तर्कों को स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने नुकसान की वसूली के लिए बोर्ड के मुकदमे को खारिज कर दिया। बोर्ड की अपील पर उच्च न्यायालय ने उसकी दलीलों को काफी हद तक सही ठहराया और मुकदमों की डिक्री की।

अपीलों को खारीज कर अभिनिर्धारित किया:

1. (ए) शर्त संख्या 8 बोलियों को टेलिग्राम द्वारा प्रत्याहारित व वापसी लेने पर प्रतिबंध करने में काफी व्यापक थी। [891H]

(ख) प्रत्यक्षतः, "बोली लगाने के संबंध में अनुदेशों" का अर्थ किसी भी अनुदेश से होगा, न केवल स्पष्टीकरण, संशोधन, बोलियों के प्रवर्धन के माध्यम से अनुदेश बल्कि बोलियों को वापस लेना या वापस लेना। टेलीग्राम द्वारा इस तरह के निर्देश स्वीकार्य नहीं होंगे। बोर्ड द्वारा निर्धारित और पालन की जाने वाली गंभीर प्रक्रिया के संबंध में, टेलीग्राम द्वारा कोई भी निर्देश जो अक्सर गुप्त होते हैं और उनके चेहरे पर प्रामाणिकता की कमी होती है, सही रूप से निषिद्ध हैं। तथ्य यह है कि बिक्री की शर्तों में कहीं भी बोलियों को वापस लेने या वापस लेने का मामला नहीं है, यही कारण होगा कि इस शर्त को व्यापक रूप से बोली वापस लेने या वापस लेने के बारे में निर्देशों के विषय को शामिल करने के रूप में माना जाना चाहिए।

2. इस तर्क में कोई बल नहीं है कि बोली वापस लेने के कारण दोनों पक्षों के बीच कोई अनुबंध संपन्न नहीं हुआ था। यह मानते हुए कि अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए दावे के अनुसार मौखिक वापसी की गई थी, तथ्य यह है कि इसे सहायक कॉफी विपणन अधिकारी को दिया गया था, जिसके पास इसे स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं था (बिक्री संचालन

अधिकारी के बजाय जो पूल नीलामी के प्रभारी थे) ने वापसी को अप्रभावी बना दिया और इसका कोई परिणाम नहीं निकला।

3. (ए) एक नीलामीकर्ता नीलामी आयोजित करने के लिए अपने स्वयं के नियम और शर्तें निर्धारित कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है, तो यह ये शर्तें हैं जो पार्टियों के अधिकारों को नियंत्रित करेंगी।

(ख) मुख्य विपणन अधिकारी को निचली बोलियों को स्वीकार करने में अपने अधिकारों के भीतर अच्छी तरह से था। जब शर्त 6 कहती है कि विक्रेता उच्चतम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह किसी भी कम बोली को स्वीकार कर सकता है। "उच्चतम" शब्दों के बाद "या कोई भी बोली" शब्दों का उपयोग इस बात पर जोर देने के लिए नहीं किया जाता है कि उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। "या किसी भी बोली" शब्द का उपयोग अनावश्यक होगा यदि एक नई नीलामी आयोजित करने का एक ही परिणाम यह सुनिश्चित करना था कि उच्चतम बोली को अस्वीकार कर दिया जाए। आवश्यक निहितार्थ द्वारा बोर्ड या उसके मुख्य विपणन अधिकारी को किसी भी उच्च बोली के बजाय कम बोली स्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई थी।

(ग) विवाद उत्पन्न होने से काफी पहले बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रथा से पता चलता है कि पूल नीलामी के पक्ष शर्त संख्या 6 को बोर्ड या उसके

मुख्य विपणन अधिकारी को उच्च बोली के बजाय कम बोली स्वीकार करने की शक्ति देने के रूप में समझते हैं। इन सबसे बढ़कर, यह शर्त डीलरों द्वारा स्टॉक को बंद करने, कीमतों को बढ़ाने और उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाने के गलत चलन को समाप्त करने के लिए तैयार की गई थी।

4. (क) हानि के शमन के प्रश्न पर कानून में अच्छी तरह से स्वीकृत स्थिति यह है कि यह अनुबंध के उल्लंघन में पार्टी को कोई अधिकार नहीं देता है, लेकिन यह एक अवधारणा है जिसे नुकसान देते समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। चूककर्ता पक्ष से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह ऐसे कदम उठाएगा जिससे निर्दोष व्यक्ति घायल हों। अपने वैधानिक कर्तव्यों के प्रदर्शन या निर्वहन में उनके द्वारा उठाए गए कदमों को उनके खिलाफ नहीं तौला जा सकता है। प्रत्येक मामले में प्रश्न गैर-चूककर्ता पक्ष द्वारा की गई कार्रवाई की तर्कसंगतता का होगा।

इस मामले में बोर्ड द्वारा किए गए विभिन्न उपाय डीलरों द्वारा किए गए कुव्यवहार को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए थे। किसी भी स्थिति में उन्हें पूल नीलामी में चूककर्ता डीलरों के खिलाफ निर्देशित नहीं किया गया था। पिछली नीलामी में बिक्री संचालन अधिकारी ने डीलरों द्वारा दी गई उच्च बोली के वरीयता में कम बोलियों को स्वीकार करने का फैसला किया, जिन्होंने इस तरह के तरीके के खिलाफ उनके द्वारा जारी मौखिक चेतावनी के बावजूद, महीने के लिए औसत कीमतों से अधिक

बोली की पेशकश की। यही कारण था कि पुनर्विक्रय पर प्राप्त कीमतें पहले पूल नीलामी में अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई कीमतों से कम थीं। किसी भी दर पर पुनः बिक्री पर, केवल उच्चतम बोलियां स्वीकार की गईं और इसलिए, पुनः बिक्री से उत्पन्न नुकसान अवास्तविक नहीं था जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा दावा किया गया था।

(ख) इस मामले के तथ्यों के आधार पर उचित समय के भीतर पुन बिक्री की गई थी।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं 2567-2568/1969

मद्रास उच्च न्यायालय के अपील संख्या 260/58 और 165/60 में दिनांकित 19-7-1963 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से- एसवी गुप्ते, एसएस जावली और एम वीरप्पा।

प्रतिवादी की ओर से- सुंदरन स्वामी, रवींद्र स्वामी और केजे जॉन।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डी वी तुलजापुरकर ने दिया।

**न्यायमूर्ति तुलजापुरकर,-**

ये अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों द्वारा को इसके सामान्य निर्णय और 19 जुलाई, 1963 को क्रमशः 1958 के ए. एस. सं. 260 और 1960 के ए. एस. सं. 165 में दो फरमानों के खिलाफ निर्देश दिया जाता है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने क्रमशः दो अपीलार्थियों

(एम. लाचिया सेट्टी एंड संस लिमिटेड और गिरी कॉफी वर्क्स) के खिलाफ हर्जाने में प्रतिवादी मुकदमों (ओ. एस. सं. <आई. डी. 1 और ओ. एस. सं. 316/1955) का फैसला सुनाया।

प्रतिवादी (कॉफी बोर्ड, बेंगलोर) कॉफी अधिनियम, 1942 के तहत निगमित एक सांविधिक निकाय है, जिसका कॉफी व्यापार, आंतरिक और बाहरी पर पूर्ण नियंत्रण लगभग एकाधिकार है। इसके कार्यों और कर्तव्यों के लिए इसे सभी संबंधितों, उत्पादक, बगान मालिक, लाइसेंस प्राप्त किसान, व्यापारी और उपभोक्ता के हित के संबंध में कॉफी की कीमतों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। अन्य बातों के साथ-साथ, इसे कॉफी बागानों के सभी मालिकों द्वारा वितरित कॉफी का विपणन करने का कर्तव्य सौंपा गया है और इस उद्देश्य के लिए इसे निर्यात और आंतरिक व्यापार के बीच कॉफी का आवंटन करने का अधिकार है और भौतिक समय पर बाद की श्रेणी को किए गए कॉफी आवंटन के संबंध में इसने आंतरिक खपत के लिए व्यापार के लिए कॉफी जारी करने के लिए तीन तरीकों को अपनाया है: (1) बंगलौर, कोयम्बटूर और मद्रास और मैसूर राज्यों के कतिपय अन्य केन्द्रों में आयोजित पूल नीलामी (थोक) नामक बिक्री द्वारा, (2) खुदरा बिक्री द्वारा जिसे "स्थानीय नीलामी" के रूप में जाना जाता है और (3) सहकारी समितियों और उसके द्वारा स्थापित प्रचार केंद्रों को बिक्री द्वारा। इन अपीलों में हम पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाली आंतरिक बिक्री से संबंधित हैं, अर्थात्, "पूल नीलामी" के माध्यम से समय-समय पर की जाने



वाली बिक्री। बेशक, ऐसी पूल नीलामी में केवल प्रतिवादी बोर्ड के साथ पंजीकृत डीलर, जिन्हें परमिट जारी किए जाते हैं, भाग लेने के हकदार होते हैं और ऐसी "पूल नीलामी" अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी बोर्ड द्वारा निर्धारित विशेष शर्तों द्वारा शासित होती हैं, जो आम तौर पर ऐसी बिक्री को विनियमित करने के लिए होती हैं जिन्हें 'बिक्री की शर्तें' कहा जाता है। (प्रदर्श-ए 3 की प्रति प्रस्तुत की)

7 अक्टूबर, 1952 को कोयम्बटूर में आयोजित "पूल नीलामी" में प्रतिवादी द्वारा 315 लॉट में शामिल कॉफी की विभिन्न मात्राओं (विभिन्न ग्रेड और गुणवत्ता की) को बिक्री के लिए रखा गया था, नीलामी मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी द्वारा स्वयं बिक्री संचालन अधिकारी के रूप में आयोजित की जा रही थी। उस नीलामी में दो अपीलकर्ताओं (एम. लचिया सेट्टी एंड संस लिमिटेड और मैसर्स गिरी कॉफी वर्क्स) सहित कई पंजीकृत डीलरों ने भाग लिया और इस उद्देश्य के लिए रखे गए बोली बक्से में कुछ लॉट के लिए निर्धारित प्रपत्रों में अपनी बोली दर्ज की। नीलामी के परिणाम की घोषणा 8 अक्टूबर, 1952 को अपराह्न 2 बजे के कुछ समय बाद और अन्य बातों के साथ-साथ की गई थी। जिन लॉटों के लिए उन्होंने अपनी बोली प्रस्तुत की थी, उनकी मात्रा के संबंध में दोनों अपीलकर्ताओं की बोलियों को मुख्य विपणन अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, हालांकि पांच लॉट के संबंध में कुछ बोलियां उच्चतम नहीं थीं, और उन्हें सफल बोलीदाता घोषित किया गया था। अपीलकर्ताओं द्वारा 17 दिनों की

निर्धारित अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर लॉट की डिलीवरी के लिए भुगतान करने और लेने में विफलता पर, प्रतिवादी बोर्ड ने 18 दिसंबर, 1952 को अपीलकर्ताओं और अन्य को पुनः बिक्री का नोटिस जारी करने के बाद, जिन्होंने इसी तरह से चूक की थी, 23 दिसंबर, 1952 को फिर से बिक्री (एक और पूल नीलामी) आयोजित की, जिस पर काफी कम कीमत वसूल की गई और प्रतिवादी बोर्ड ने दो अपीलकर्ताओं सहित चूककर्ता बोलीदाताओं के खिलाफ 15 मुकदमों का एक बैच दायर किया। मुकदमा संख्या 319/1955 में, जो अपीलकर्ता एम. लचिया सेट्टी एंड संस लिमिटेड के खिलाफ दायर किया गया था, पुनः बिक्री के परिणामस्वरूप हुए नुकसान को नुकसान के रूप में 34,570-6-6 रुपये का दावा किया गया था और अपीलकर्ता मैसर्स गिरी कॉफी वर्क्स के खिलाफ दायर मुकदमा संख्या 316/1955 में 5,917 रुपये के नुकसान का दावा किया गया था।

अपीलकर्ताओं ने अपने लिखित कथनों के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, तीन प्रमुख बचाव उठाए। सर्वप्रथम, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके मामले में उन्होंने परिणामों की घोषणा से पहले 7 अक्टूबर, 1952 को मौखिक रूप से और साथ ही टेलीग्राम द्वारा अपनी बोली रद्द कर दी थी और इसलिए उनके और कॉफी बोर्ड के बीच कोई अनुबंध समाप्त नहीं हुआ था और इसलिए, उन्हें फिर से बिक्री पर होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा, यह तर्क दिया गया था कि नीलामी में कम बोली हमेशा उच्च बोली प्राप्त होने पर समाप्त हो जाती है

और इस प्रकार निचली बोली स्वीकृति के लिए असमर्थ हो जाती है और यहां तक कि 'बिक्री की शर्तों' की शर्त संख्या 6 के तहत भी बोर्ड या उसके मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी के पास अपनी कम बोली (गिरि कॉफी वर्क्स के मामले में 5 लॉट के संबंध में) स्वीकार करने की कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वे संबंधित लॉट के लिए उच्चतम बोलियां नहीं थी। तीसरा, यह तर्क दिया गया था कि कॉफी बोर्ड ने कॉफी की कीमतों को जानबूझकर कम कर दिया था या नुकसान का दावा करने के लिए स्वयं को अयोग्य घोषित कर दिया था क्योंकि इस तरह की पुनः बिक्री पर होने वाला नुकसान अवास्तविक था और किसी भी स्थिति में अत्यधिक देरी के बाद पुनः बिक्री आयोजित की गई थी, अपीलकर्ता दावा किए गए नुकसान की मात्रा के लिए उत्तरदायी नहीं थे। मुकदमों में उठाए गए अन्य बचावों को निर्धारित करना अनावश्यक है क्योंकि इन अपीलों में अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा हमारी स्वीकृति के लिए केवल उपरोक्त तीन दलीलों पर जोर दिया गया था।

प्रतिवादी ने अपनी प्रत्युत्तर में अपीलकर्ताओं की उपरोक्त दलीलों का खंडन किया। यह इंगित किया गया कि "पूल नीलामी" को नियंत्रित करने वाली शर्त संख्या 8 के तहत किसी भी बोली को टेलीग्राफिक रूप से वापस लेने या वापस लेने की अनुमति नहीं थी और उचित अधिकारी को मौखिक अस्वीकृति नहीं की गई थी और इसलिए, कोई वैध वापसी नहीं होने के कारण अपीलकर्ताओं की बोलियों को उचित रूप से स्वीकार किया गया था,

जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त हो गए थे। इस बात से इनकार किया गया कि "पूल नीलामी" बिक्री में प्रतिवादी बोर्ड केवल उच्चतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य था: दूसरी ओर, यह तर्क दिया गया था कि उच्चतम बोली के वरीयता में किसी भी कम बोली को स्वीकार करने की शक्ति शर्त संख्या 6 में निहित थी, विशेष रूप से सभी संबंधितों के हित में कॉफी की कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए प्रतिवादी बोर्ड द्वारा देय कर्तव्य के संबंध में। प्रतिवादी ने आगे इस बात से इनकार किया कि उसने इस तरह की पुनः बिक्री के समय कीमतों में गिरावट के कारण पुनः बिक्री पर होने वाले नुकसान का दावा करने से खुद को वंचित कर लिया था या यह कि हुआ नुकसान अवास्तविक था। इसमें कहा गया है कि कॉफी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उसके द्वारा किए गए उपाय आवश्यक हो गए थे क्योंकि कुछ पंजीकृत डीलर और उनके कुछ दोस्तों ने खुद को एक रिंग में बना लिया था और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने लिए गैरकानूनी लाभ कमाने के उद्देश्य से कीमतों में वृद्धि करके कॉफी पर कब्जा कर लिया था। उसने इस बात से भी इनकार किया कि पुनः बिक्री में कोई देरी हुई।

पक्षकारों ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का प्रस्तुत किया और पूरी सामग्री की विवेचना पर विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए उपरोक्त प्रतिरक्षा को स्वीकार कर लिया और 31 मार्च, 1958 के एक सामान्य फैसले द्वारा खर्च के साथ मुकदमों को खारिज कर दिया। प्रतिवादी

कॉफी बोर्ड ने उच्च न्यायालय में अपील को प्राथमिकता दी और 19 जुलाई, 1963 के अपने सामान्य फैसले से उच्च न्यायालय ने अपीलों की अनुमति दी और अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रतिवादी के दावों का फैसला किया। उच्च न्यायालय ने माना कि शर्त संख्या 8 के तहत, टेलीग्राफिक निकासी या बोली वापस लेने पर रोक लगा दी गई थी और दोनों अपीलकर्ताओं (एम. लचिया सेट्टी एंड संस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में और मेसर्स गिरी कॉफी वर्क्स के भागीदार के रूप में) की ओर से सहायक अधिकारी को एम. एल. गोपाल सेट्टी द्वारा मौखिक रूप से वापस लेने का कोई फायदा नहीं हुआ और, इसलिए, अपीलकर्ताओं की बोलियों को उचित रूप से स्वीकार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त हो गए थे। इसने आगे विचार किया कि बिक्री की शर्तों की शर्त संख्या 6 बोर्ड को उच्चतम बोली के वरीयता में किसी भी कम बोली को स्वीकार करने के लिए एक निहित शक्ति प्रदान करती है और तत्काल मामले में प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी को उच्चतम बोली के बजाय कम बोली स्वीकार करने में उचित ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी बोर्ड द्वारा दावा किए गए नुकसान के संबंध में अपीलकर्ताओं की दलीलों को खारिज कर दिया और अपीलकर्ताओं से उसके द्वारा दावा की गई राशि का फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में पारित इन आदेशों को अपीलकर्ताओं द्वारा इन अपीलों में हमारे समक्ष चुनौती दी जा रही है।

अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा अपीलों के समर्थन में उठाया गया पहला तर्क यह था कि नीलामी के परिणाम दोपहर 2 बजे के बाद घोषित किए जाने से पहले। 8 अक्टूबर, 1952 को, अपीलकर्ताओं ने मौखिक रूप से और साथ ही टेलीग्राम द्वारा अपनी बोली वापस ले ली थी और इसलिए, उनकी बोली उसके बाद स्वीकार नहीं की जा सकती थी और एक तरफ अपीलकर्ताओं और दूसरी तरफ कॉफी बोर्ड के बीच कोई संपन्न अनुबंध नहीं हुआ था। इस संबंध में वकील द्वारा रिकॉर्ड से उभरने वाले दो तथ्यात्मक पहलुओं पर भरोसा रखा गया था। उन्होंने बताया कि एम. लचिया सेट्टी एंड संस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मैसर्स गिरी कॉफी वर्क्स के साझेदार के रूप में एम. एल. गोपाल सेट्टी (डी.डब्ल्यू.1) ने 7 अक्टूबर, 1952 (प्रदर्श बी-22) को मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी, कॉफी बोर्ड, कोयम्बटूर को संबोधित करते हुए इस आशय का एक टेलीग्राम भेजा था, "इसके द्वारा गिरि कॉफी वर्क्स और मैसूर लचिया सेट्टी एंड संस लिमिटेड की ओर से आज दी गई सभी बोलियों को वापस लिया जाता है। इसे शुरू में सहायक कॉफी विपणन अधिकारी एफ. एम. सल्थाना (पी.डब्ल्यू.1) ने 8 अक्टूबर, 1952 को लगभग 12.30 बजे (मध्यरात्रि) अपने कार्यालय में प्राप्त किया था और उसके बाद 8 अक्टूबर, 1952 को लगभग 12.30 बजे मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी (पी.डब्ल्यू.3) श्री कुट्टलिंगम पिल्लई द्वारा प्राप्त किया गया था, जो परिणामों की घोषणा से बहुत पहले था। दूसरा, उन्होंने बताया कि सल्थाना (पी.डब्ल्यू. 1) ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि 8

अक्टूबर, 1952 को परिणाम घोषित होने से पहले एमएल गोपाल सेट्टी सहित कई डीलर कार्यालय में इंतजार कर रहे थे और उस समय गोपाल सेट्टी ने उनसे पूछा कि क्या मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी को उनका टेलीग्राम प्राप्त हुआ है, जिसका उन्होंने हां में जवाब दिया, लेकिन गोपाल सेट्टी को बताया कि बोर्ड बोलियों के संबंध में टेलीग्राम का संज्ञान नहीं ले सकता है। इसके बाद गोपाल सेट्टी ने कहा कि वह उन्हें (सल्धाना) टेलीग्राम की पुष्टि के लिए मौखिक निर्देश दे रहे थे, जिस पर सल्धाना ने जवाब दिया कि वह (सल्धाना) बिक्री संचालन अधिकारी नहीं थे और बोली वापस लेने या वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बोली को बिक्री संचालन अधिकारी, जिसका अर्थ है मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था। इस तरीके से अपीलकर्ताओं ने दलील दी कि उन्होंने नीलामी के परिणामों की घोषणा से पहले अपनी बोली वापस ले ली थी। दूसरी ओर, प्रतिवादी बोर्ड के वकील ने बिक्री की शर्तों की शर्त संख्या 8 पर भरोसा किया, जिसके तहत उन्होंने टेलीग्राफिक वापसी या बोली वापस लेने का आग्रह किया था और मौखिक वापसी के संबंध में यह तर्क दिया गया था कि उचित अधिकारी, अर्थात् मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी, को नहीं दिया गया था, जिसका कोई लाभ नहीं हुआ।

इसलिए, शर्त संख्या 8 पर विचार करना आवश्यक होगा क्योंकि इसके उचित गठन पर इस सवाल पर निर्भर करेगा कि क्या टेलीग्राफिक निकासी या बोलियों को वापस लेना निषिद्ध था या नहीं? 'पूल नीलामी' को

नियंत्रित करने वाली बिक्री की शर्तों की एक प्रति प्रदर्श ए -3 प्रस्तुत की गई थी। प्रारंभ में, यह देखा जाना चाहिए कि कॉफी बोर्ड द्वारा आयोजित "पूल नीलामी" सामान्य सार्वजनिक नीलामियों के विपरीत हैं, जहां प्रतिस्पर्धी बोली आमतौर पर सभी बोलीदाताओं की सुनवाई के भीतर खुले तौर पर दी जाती है ताकि कोई भी बोलीदाता यह जानने के बाद कि पहले की बोली क्या है, उच्च बोली देकर इसमें सुधार कर सकता है। कॉफी बोर्ड द्वारा आयोजित "पूल नीलामी" में केवल बोर्ड से अपेक्षित परमिट रखने वाले पंजीकृत डीलरों को भाग लेने की अनुमति दी जाती है और बोली देने के कार्य के साथ कुछ गंभीरता जुड़ी होती है क्योंकि शर्त संख्या 1 में प्रावधान है कि प्रतिभागी बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने कोटेशन (बोलियां) प्रस्तुत करेंगे और निर्धारित प्रपत्र में बोलियों को बंद और सील किए गए इस उद्देश्य के लिए रखे गए बोली बॉक्स में दर्ज किया जाना अपेक्षित है। और बोली की समाप्ति पर, बक्से खोले जाते हैं और बिक्री संचालन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर के तहत उनका रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसे बोलीदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा भी सत्यापित किया जाता है; इसके बाद बोलियों को सारणीबद्ध किया जाता है और बिक्री संचालन अधिकारी बोलियों का चयन करता है और सफल बोलीदाताओं को आवंटन करता है और सफल बोलीदाताओं के नामों के साथ उन्हें आवंटित लॉट और मात्रा सहित एक घोषणा बोर्ड के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है। वास्तव में "पूल नीलामी" निविदा आमंत्रित करके बिक्री के समान या



अधिक समान हैं। यह ऐसी निर्विवाद प्रक्रिया के संदर्भ में है जिसका "पूल नीलामी" आयोजित करने के मामले में गंभीरता से पालन किया जाता है कि शर्त संख्या 8 पर विचार करना होगा। यह इस प्रकार है:

"8. बोली के संबंध में टेलीग्राफिक बोली या टेलीग्राफिक निर्देशों पर विचार नहीं किया जाएगा।"

प्रश्न यह है कि क्या उपर्युक्त स्थिति में होने वाला वाक्यांश "बोली के संबंध में टेलीग्राफिक निर्देश" इतना व्यापक है कि इसमें बोलियों को वापस लेने या वापस लेने से संबंधित निर्देश शामिल हैं? अपीलकर्ताओं के वकील के अनुसार, वाक्यांश केवल बोली लगाने या देने के बारे में निर्देशों को संदर्भित करता है या उच्चतम स्तर पर पहले से दी गई बोलियों के स्पष्टीकरण या संशोधन के माध्यम से निर्देश शामिल होंगे, जो टेलीग्राफिक संचार द्वारा अनुज्ञेय नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि बोली वापस लेने या वापस लेने या रद्द करने के विषय को बिक्री की शर्तों में कहीं और नहीं देखा गया है और इसलिए, टेलीग्राम द्वारा वापसी या वापसी के खिलाफ किसी भी विशिष्ट या स्पष्ट प्रतिबंध के अभाव में, टेलीग्राम द्वारा वापसी या वापसी की सूचना देने के सामान्य कानून के तहत सामान्य तरीका अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। उनके अनुसार, वापसी के संचार के सामान्य तरीके की कटौती, जो सामान्य कानून के तहत एक प्रस्तावकर्ता के लिए खुली है, कुछ स्पष्ट प्रावधान द्वारा होनी चाहिए या आवश्यक

निहितार्थ द्वारा उत्पन्न होनी चाहिए। शर्त संख्या 8 में होने वाले संबंधित वाक्यांश पर अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा रखे गए निर्माण को स्वीकार करना संभव नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस शर्त के पहले भाग में टेलीग्राफिक बोलियां देने पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी गई थी, वाक्यांश "बोली के संबंध में टेलीग्राफिक निर्देश" फिर से बोली देने या बनाने के कार्य के संबंध में निर्देशों का उल्लेख नहीं कर सकता है। दूसरा, ऊपरी तौर पर 'बोली के संबंध में अनुदेशों' का अर्थ किसी भी अनुदेश से होगा, न केवल स्पष्टीकरण, संशोधन, बोलियों के प्रवर्धन के माध्यम से अनुदेश बल्कि बोलियों को वापस लेना या वापस लेना और टेलीग्राम द्वारा ऐसे निर्देश अस्वीकार्य होंगे। इसके अलावा, कॉफी बोर्ड द्वारा अपनी पूल नीलामी आयोजित करने के मामले में निर्धारित और अपनाई गई गंभीर प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, बोली निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत करना आवश्यक है और टेलीग्राफिक बोलियां निषिद्ध हैं, इसका कारण यह है कि ऐसी बोलियों से संबंधित कोई भी अनुदेश, चाहे स्पष्टीकरण, प्रवर्धन, संशोधन, रद्दीकरण या वापसी के माध्यम से, टेलीग्राम द्वारा अनुमत नहीं होना चाहिए जो अक्सर छिपे हुये होते हैं और जिनपर प्रत्यक्षता पर प्रामाणिकता नहीं होती है। इसके अलावा, तथ्य यह है कि बिक्री की शर्तों में कहीं भी बोली को वापस लेने या वापस लेने का विषय नहीं है, यही कारण होगा कि शर्त संख्या 8 को व्यापक रूप से बोली वापस लेने या वापस लेने के बारे में निर्देशों के विषय के रूप में माना जाना चाहिए। हमारे विचार में, उच्च

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि शर्त संख्या 8 टेलीग्राम द्वारा बोलियों को वापस लेने या वापस लेने पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त व्यापक थी।

8 अक्टूबर, 1952 को एमएल गोपाल सेट्टी द्वारा किए गए मौखिक प्रत्याहार की ओर रुख रखते हुए, उच्च न्यायालय ने विचार किया है कि परिणाम घोषित होने से पहले मौखिक प्रत्याहार का मामला सही नहीं था, जिसे बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन, अगर गोपाल सेट्टी (डी.डब्ल्यू. 1) और सल्धाना (पी.डब्ल्यू. 1) की गवाही सहित इस तरह के मौखिक प्रत्याहार के बारे में साक्ष्य को इसके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, तो भी अपीलकर्ताओं को इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि, सहायक कॉफी मार्केटिंग अधिकारी सल्धाना को इस तरह के मौखिक प्रत्यावर्तन दिए गए थे, जिनके पास इस मामले में कोई अधिकार नहीं था। प्रक्रिया के तहत यह बिक्री संचालन अधिकारी है जो पूल नीलामी का प्रभारी है। इसलिए, बिक्री संचालन अधिकारी या मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी, बोर्ड के कार्यकारी प्रमुख को वापस लेना पड़ा, और यही कारण है कि अपीलकर्ताओं की ओर से मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी को टेलीग्राम प्रदर्श बी -22 को संबोधित किया गया था। इस मामले में मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी स्वयं बिक्री संचालन अधिकारी थे और मौखिक प्रत्यावर्तन उन्हें नहीं की गई थी, बल्कि इसे सल्धाना को की गयी थी, जिनके पास कोई अधिकार नहीं था। इसलिए, मौखिक प्रत्यावर्तन अप्रभावी

थी और इसका कोई परिणाम नहीं था। इसलिए, हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है कि एक तरफ उनके और दूसरी तरफ कॉफी बोर्ड के बीच उनकी बोलियों को वापस लेने या वापस लेने के कारण कोई अनुबंध नहीं हुआ था।

अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा आग्रह किया गया अगला तर्क यह था कि मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी के पास कम बोली स्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं थी, जब अन्य प्रतिभागियों द्वारा उच्च बोली प्रस्तुत की गई थी, क्योंकि उनके अनुसार, नीलामी बिक्री में सामान्य स्थापित नियम यह रहा है कि उच्च बोली प्राप्त होने पर कम बोली समाप्त हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कम बोली स्वीकृति में असमर्थ हो जाती है। उन्होंने आगे आग्रह किया कि बिक्री की शर्तों की शर्त संख्या 6 के तहत भी, जिस पर प्रतिवादी बोर्ड ने भरोसा करने की मांग की थी, बोर्ड या उसके मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी को कम बोली स्वीकार करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है, क्योंकि, शर्त संख्या 6 यह है कि यह बोर्ड को उच्चतम या किसी भी बोली को स्वीकार करने के दायित्व से मुक्त करता है और बोर्ड को ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। वकील ने निष्पक्ष रूप से कहा कि जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, यह विवाद गिरि कॉफी वर्क्स के लिए उपलब्ध था और वह भी केवल 5 लॉट के संबंध में इसकी बोलियों के संबंध में, क्योंकि, गिरि कॉफी वर्क्स द्वारा दी गई अन्य बोलियों के मामले में और एम. लचिया सेट्टी एंड संस लिमिटेड द्वारा दी

गई सभी बोलियां जो स्वीकार की गई थीं, वे उच्चतम बोलियां थीं। इस विवाद के समर्थन में वकील ने हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों (4 वां संस्करण) खंड 9, पृष्ठ 102 पर पैरा 231 में होने वाले कानून के निम्नलिखित कथन पर भरोसा किया:

"231 नीलामी- नीलामी की बिक्री में, यह एक लंबे समय से स्थापित नियम है कि प्रथम दृष्टया नीलामीकर्ता का बोली के लिए अनुरोध केवल एक निमंत्रण है, और प्रत्येक बोली एक प्रस्ताव का गठन करती है जिसे नीलामीकर्ता द्वारा विक्रेता की ओर से स्वीकार किया जाता है। वह सामान्य तरीके से अपनी स्वीकृति का प्रतीक है। इसके अलावा, ऐसा लगता है कि उच्च बोली लगाते ही प्रत्येक बोली समाप्त हो जाती है।....."

यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि कथन का रेखांकित भाग ब्लैकबियर्ड बनाम लीन्डीग्रेन के मामले द्वारा समर्थित है, जिसका संदर्भित फुटनोट 3 में किया। [(1786) 1 कॉक्स ईक्यू केस 205 = 29 इंग्लिश रिपोर्ट चांसरी) 1130]। यह एक ऐसा मामला था जहां ऋण के भुगतान के लिए मालिक के सामने एक संपत्ति बेची गई थी और ए को 13,000 रुपये की राशि में सबसे अच्छा बोलीदाता बताया गया था, लेकिन रिपोर्ट की पुष्टि होने से पहले यह पता चला कि बोली के समय ए पागल था। अदालत को इस

कारण से सभी पक्षों की ओर से पेश किया गया था कि अगले सबसे अच्छे बोलीदाता बी को उसके द्वारा बोली गई राशि पर खरीदार के रूप में रिपोर्ट किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के लिए बी ने सहमति व्यक्त की लेकिन अदालत ने सोचा कि यह अनियमित था और संपत्ति को आम तौर पर फिर से बेचने का निर्देश दिया। इस फैसले पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि सामान्य नियम यह था कि उच्च बोली प्राप्त होने पर कम बोली समाप्त हो जाती है, और यदि किसी कारण से उच्चतम बोली स्वीकार नहीं की जाती है, तो नीलामी को छोड़ दिया जाना चाहिए और नए सिरे से नीलामी आयोजित करने की आवश्यकता होगी और इसलिए, इस मामले में मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी गिरि कॉफी वर्क्स की पाँच लॉट के संबंध में कम बोली को स्वीकार नहीं कर सकता है।

प्रतिवादी बोर्ड के वकील ने कानून के उपर्युक्त कथन पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि यह नीलामी को नियंत्रित करने वाले नीलामीकर्ता द्वारा निर्धारित विशेष शर्तों के अभाव में आम तौर पर नीलामी पर लागू होता है। उनके अनुसार यह अच्छी तरह से तय था कि एक नीलामीकर्ता अपने स्वयं के नियमों और शर्तों को निर्धारित कर सकता है जिसके आधार पर संपत्ति नीलामी द्वारा बिक्री के लिए उजागर होती है, और उस अवसर में, उसके द्वारा निर्धारित विशेष शर्तें स्थिति को नियंत्रित करेंगी। उन्होंने शर्त संख्या 6 पर दृढ़ता से भरोसा किया, क्योंकि बोर्ड द्वारा आयोजित "पूल नीलामी" को नियंत्रित करने वाली एक विशेष शर्त है और

उक्त शर्त बोर्ड या उसके मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी को प्राप्त होने वाली किसी भी उच्च बोली के बजाय कम बोली स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करती है। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि नीलामीकर्ता नीलामी आयोजित करने के लिए अपने नियम और शर्तें निर्धारित कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है तो वे शर्तें पक्षकारों के अधिकारों को नियंत्रित करेंगी। हमारे विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या शर्त संख्या 6 में किसी भी उच्च बोली के लिए वरीयता में कम बोली स्वीकार करने की शक्ति शामिल है?

शर्त संख्या 6 इस प्रकार है:

"(6) विक्रेता उच्चतम या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है। वह अपने फैसले के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं हैं, और उनका निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।"

अपीलकर्ता के वकील ने आग्रह किया कि शर्त संख्या 6 की भाषा यह नहीं दर्शाती है कि विक्रेता यानी प्रतिवादी बोर्ड को कोई शक्ति प्रदान करने का आशयित था, लेकिन यह बोर्ड को उच्चतम बोली स्वीकार करने के दायित्व से मुक्त करने से संबंधित है, यह कहते हुए कि विक्रेता उच्चतम बोली स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और इस तरह की गैर-स्वीकृति के लिए वह कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा,

शर्त यह है कि विक्रेता उच्चतम या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यह नहीं कहता है कि विक्रेता उस निचली बोली को स्वीकार कर सकता है। उनके अनुसार, "या कोई भी बोली" शब्द जो "उच्चतम" शब्दों का अनुसरण करते हैं, केवल इस पहलू पर जोर देते हैं कि उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि बोर्ड या उसके मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी को उच्च बोली के बजाय किसी भी कम बोली को स्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है, इसलिए सामान्य नियम लागू होता है और पांच लॉट को उस नीलामी से वापस ले लिया जाना चाहिए था और नए सिरे से नीलामी के लिए रखा जाना चाहिए था। हम शर्त संख्या 6 के उचित गठन के सवाल पर अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा दी गई प्रस्तुतियों से प्रभावित नहीं हैं। यह सच है कि शर्त संख्या 6 को एक अजीब तरीके से पेश किया गया है, लेकिन जब यह बताया कि विक्रेता उच्चतम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, तो इसका अर्थ है कि वह किसी भी निचली बोली को स्वीकार कर सकता है। "उच्चतम" शब्दों के बाद "या किसी भी बोली" शब्दों को जोड़ना हमें कुछ महत्व का लगता है। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि इन शब्दों का उपयोग केवल इस पहलू पर जोर देने के उद्देश्य से किया जाता है कि उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा विचार है कि दो अलग-अलग शक्तियां- उच्चतम बोली को अस्वीकार करने की शक्ति और किसी भी बोली को अस्वीकार करने की



शक्ति- अलग-अलग परिणामों के साथ विक्रेता को इस शर्त द्वारा प्रदान किए जाने का इरादा है। "या किसी भी बोली" शब्द को जोड़ना अनावश्यक होगा यदि उच्चतम बोली को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में एक ही परिणाम (नई नीलामी आयोजित करने का) सामने आता है। इसलिए, शर्त के गठन पर यह स्पष्ट है कि आवश्यक निहितार्थ द्वारा बोर्ड या उसके मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी को किसी भी उच्च बोली के बजाय कम बोली स्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसके अलावा, प्रदर्श ए-275 में प्रतिवादी बोर्ड ने एक सारणीबद्ध विवरण प्रस्तुत किया है जिसमें 1949 से 1952 तक उसके द्वारा आयोजित "पूल नीलामी" में उच्चतम बोलियों को अस्वीकार कर दिया गया था और कम बोलियों को स्वीकार किया गया था- एक तात्कालिक विवाद उत्पन्न होने से बहुत पहले की अवधि जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि पूल नीलामी के पक्षकारों ने शर्त संख्या 6 को बोर्ड या उसके मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी को उच्च बोलियों की तुलना में कम बोलियां स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करने के रूप में भी समझा। इसके अलावा, शर्त संख्या 6 का ऐसा निर्माण कॉफी की कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखते हुए उन्हें नियंत्रित करने के लिए बोर्ड के मुख्य कार्य की उपलब्धि के अनुरूप होगा क्योंकि किसी भी उच्च या उच्चतम बोली के लिए वरीयता में कम बोली स्वीकार करने का अधिकार कॉफी डीलरों की चेन या सिंडिकेट के गठन से कॉफी की खरीद, उनके द्वारा कीमतों में वृद्धि आदि जैसे कदाचार से बचने में मदद करती है। शर्त संख्या 6 पर हम जो

विचार कर रहे हैं, उसमें यह स्पष्ट है कि इस मामले में मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में थे जब उन्होंने गिरि कॉफी वर्क्स से 5 लॉट के संबंध में प्राप्त कम बोलियों को स्वीकार किया था। इसलिए, इस संबंध में अपीलकर्ताओं की दलील विफल होनी चाहिए।

प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए नुकसान की मात्रा पर अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा आग्रह की गई अंतिम दलील में कॉफी के डिफॉल्ट लॉट के संबंध में आयोजित पुनः बिक्री के खिलाफ दो तरफा हमला शामिल था। सबसे पहले, बोर्ड पूल नीलामी में उन्हें आवंटित कॉफी का भुगतान करने और डिलीवरी लेने में अपीलकर्ताओं की ओर से होने वाले नुकसान को कम करने या कम करने के लिए बाध्य था, लेकिन इसके बजाय बोर्ड द्वारा कॉफी की कीमतों को कम करने के लिए जानबूझकर कदम उठाए गए और फिर 23 दिसंबर को फिर से बिक्री की गई। 1952 के परिणामस्वरूप क्रमशः 34,570-6-6 रुपये और 5,917 रुपये का कथित नुकसान हुआ, जिसे घटनाओं के सामान्य क्रम में उल्लंघन से प्रत्यक्ष और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नुकसान के रूप में नहीं माना जा सकता था, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अवास्तविक, बनाया और लाया गया था और इसलिए, यह अपीलकर्ताओं से वसूल करने योग्य नहीं था। दूसरा, पुनः बिक्री उल्लंघन के उचित समय के भीतर नहीं की गई थी, बल्कि इसमें अत्यधिक देरी हुई थी और इसलिए, अपीलकर्ता दावा की गई मात्रा के लिए उत्तरदायी नहीं थे। यह कहा जा सकता है कि चूककर्ता कॉफी को निर्यात नीलामी में बिक्री के लिए

रखा जाना चाहिए था, न कि पूल नीलामी में, हालांकि निचली अदालतों में आग्रह किया गया था, हमारे समक्ष नहीं रखा गया था। वर्तमान में हम जिन कारणों का उल्लेख करेंगे, उनमें से किसी में भी हमें आक्रमण के इन दो आधारों में से किसी में भी कोई आधार नहीं मिलता है।

प्रारंभ में यह देखा जाना चाहिए कि हानि के शमन का सिद्धांत उस पक्ष को कोई अधिकार नहीं देता है जो अनुबंध का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन यह एक अवधारणा है जिसे नुकसान देते समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संबंध में कानून का सही कथन हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानून (4 वां संस्करण) खंड 12, पैरा 1193 में पृष्ठ 477 पर पाया जा सकता है जो इस प्रकार चलता है:

"1193. नुकसान को कम करने के लिए वादी का कर्तव्य। वादी को उस नुकसान को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए जो उसे प्रतिवादी की गलती के परिणामस्वरूप हुआ है, और, यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह ऐसे किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता है, जिसे उसे उचित रूप से टालना चाहिए था।"

पुनः, पृष्ठ 478 पर पैरा 1194 में निम्नलिखित कथन 'वादी के लिए अपेक्षित आचरण का मानक' शीर्षक के तहत आता है:

"वादी को केवल यथोचित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, और क्या उसने ऐसा किया है, यह प्रत्येक विशेष मामले की परिस्थितियों में तथ्य का प्रश्न है, न कि विधि का प्रश्न। उसे न केवल अपने हितों में बल्कि प्रतिवादी के हितों में भी कार्य करना चाहिए और नुकसान को कम रखना चाहिए, जहां तक यह उचित और उचित हो....."

अनुबंध के उल्लंघन के मामले में वादी व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम के अलावा कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है, और जहां उसे परेशानी की स्थिति में रखा गया है, स्वयं को निकालने के लिए उसे जो उपाय अपनाने के लिए किया जा सकता है, उसे प्रतिवादी के कहने पर अच्छे पैमाने पर नहीं तौला जाना चाहिए, जिसके अनुबंध के उल्लंघन ने कठिनाई उत्पन्न की हो.

वादी, प्रतिवादी द्वारा देय नुकसान को कम करने के लिए, अपनी संपत्ति को नष्ट करने के लिए या खुद को या उसकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा, वादी को ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है जो निर्दोष व्यक्तियों को घायल कर दें। (बल दिया गया)।

बैंको डी पुर्तगाल बनाम वाटरलॉ एंड संस, लिमिटेड, लॉर्ड शैंकी, एल.सी., ने जेम्स फिनले एंड कंपनी बनाम एनवी क्विक हू टॉग, मॉडेल

मात्चापिज में प्रतिपादित विधि के कथन को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया, "इंग्लैंड में, यह कानून है कि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नुकसान को कम करने के लिए बाध्य नहीं है, जिसने अनुबंध भंग किया है, अगर ऐसा करने से वह व्यापार में खराब नाम प्राप्त करके अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। अमेरिकी न्यायशास्त्र 2 में, खंड 22 पैरा 33 (पेज 55-56 पर) में कानून का निम्नलिखित कथन शामिल है:

" 33. परिहार्य परिहार्य परिणामों का सामान्य सिद्धांत के उल्लंघन के लिए कार्रवाई में नुकसान के माप पर लागू होता है अनुबंध। इस प्रकार, गैर-चूककर्ता को दिए गए नुकसान एक अनुबंध के लिए पक्ष निर्धारित किया जाएगा और मापा जाएगा जैसे कि उस पक्ष ने नुकसान से बचने के लिए उचित प्रयास किए थे डिफॉल्ट के परिणामस्वरूप। कुछ अदालतों ने यह कहा है निर्दोष पक्ष द्वारा देय कर्तव्य के संदर्भ में सिद्धांत एक डिफॉल्ट रूप से; अर्थात्, वह व्यक्ति जो हर्जाने की मांग कर रहा है अनुबंध के उल्लंघन के लिए उन नुकसानों को कम से कम करना कर्तव्य है।"

हालांकि, विश्लेषण पर, यह स्पष्ट है कि अनुबंध के मामलों में भी आम तौर पर, नुकसान को कम करने का कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि नहीं

किसी को गैर-चूक करने वाले पक्ष के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है यदि वह डिफॉल्ट से उत्पन्न होने वाले कुछ परिणामों से यथोचित रूप से नहीं बचता है। इस तरह की विफलता गैर-चूक करने वाले पक्ष को मुकदमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाती है; यह केवल यह इंगित करता है कि वास्तव में हुए नुकसान कानून की भरपाई से अधिक हैं। इसलिए, अनुबंध कार्यों में, परिहार्य परिणामों का सिद्धांत केवल एक है नुकसान को कैसे मापा जाएगा, इस बारे में विवरण। (जोर दें प्रदान किया गया)।

कानून के उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गैर-चूककर्ता पक्ष से ऐसे कदम उठाने की उम्मीद नहीं की जाती है जो निर्दोष व्यक्तियों को घायल करेंगे। यदि ऐसा है, तो उसके द्वारा अपने वैधानिक कर्तव्य के निष्पादन या निर्वहन में उठाए गए कदमों को भी उसके विरुद्ध आंका नहीं जा सकता है। संक्षेप में, प्रत्येक मामले में प्रश्न गैर-चूककर्ता पक्ष द्वारा की गई कार्रवाई की तर्कसंगतता में से एक होगा।

यहां अभिलेख पर मौजूद सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वर्ष 1952 में, विशेष रूप से मार्च से अक्टूबर 1952 तक, कॉफी डीलरों द्वारा किए गए कदाचारों के कारण आंतरिक कॉफी की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गईं थीं और यहां तक कि भारत सरकार ने भी इसके बारे में बहुत चिंतित महसूस किया था और सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ कॉफी बोर्ड के सदस्यों द्वारा कॉफी की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाने के

सुझाव दिए गए थे। इस संबंध में सरकार के निदेश के अनुसरण में कॉफी बोर्ड द्वारा व्यापार और उपभोक्ता दोनों के हित में उचित स्तर और वास्तव में कॉफी के मूल्यों को विनियमित करने की दृष्टि से उच्चतर बोलियों के स्थान पर कम बोलियों को स्वीकार करने के कदम सहित अनेक उपाय किए गए थे। स्पष्ट रूप से, ये उपाय बोर्ड द्वारा सभी संबंधितों, विशेष रूप से उपभोक्ता के हित में कॉफी की कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने के अपने मुख्य कार्य और कर्तव्य के निर्वहन में किए जा रहे थे और संबंधित पूल नीलामी में चूककर्ता डीलरों के खिलाफ निर्देशित नहीं किए गए थे। वास्तव में, मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी कुट्टलिंगम पिल्लई (पी.डब्ल्यू. 3) का साक्ष्य यह रहा है कि उस दिन "पूल नीलामी" शुरू होने से पहले उन्होंने बोलीदाताओं को मौखिक चेतावनी जारी की थी कि भारत सरकार कॉफी की कीमतों में वृद्धि के बारे में चिंतित है और उन्हें कीमतों को बढ़ाने और स्टॉक को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और एम. एल. गोपाल सेट्टी (डी.डब्ल्यू 1) ने स्वीकार किया है कि मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी ने दिया था। एक चेतावनी कि उच्च बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, जब इस तरह की चेतावनी अनावश्यक रूप से जारी किए जाने के बावजूद सितंबर 1952 के महीने में प्रचलित औसत कीमतों से अधिक ऊंची बोलियां दी गईं (जो स्वयं अधिक थीं), तो मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी ने उच्च बोलियों की तुलना में कम बोलियों को स्वीकार करने का निर्णय लिया। इन परिस्थितियों में 23 दिसंबर, 1952

को आयोजित पुनः बिक्री में प्राप्त कीमतें अपीलकर्ताओं की बोली से कम थीं, जिन्हें 7 अक्टूबर, 1952 को आयोजित "पूल नीलामी" में स्वीकार किया गया था। यहां यह बताया जाना चाहिए कि पुनः बिक्री में केवल उच्चतम बोली स्वीकार की गई थी। इसलिए ऐसा नहीं है कि फिर से बिक्री के समय नुकसान को बढ़ाने के लिए जानबूझकर कम बोलियों को स्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव को स्वीकार करना असंभव है कि बोर्ड को उपभोक्ताओं की कीमत पर उच्च मूल्य स्तर को केवल इस दृष्टि से बनाए रखना चाहिए था कि चूककर्ता बोलीदाताओं को पुन बिक्री पर कोई नुकसान न हो। इसलिए, पुनर्विक्रय पर होने वाली हानि को "अवास्तविक" हानि नहीं माना जा सकता है। इस आधार पर प्रतिवादी को नुकसान की मंजूरी के खिलाफ अपीलकर्ताओं का हमला स्पष्ट रूप से अस्थिर है।

जहां तक पुनर्बिक्री में कथित देरी का संबंध है, यह देखा जाना चाहिए कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने यह विचार लिया है कि इसे सामान्य प्रक्रिया में आयोजित अगली "पूल नीलामी" में उचित समय के भीतर आयोजित किया गया था। संबंधित "पूल नीलामी" के परिणाम 8 अक्टूबर, 1952 को दोपहर 2 बजे के कुछ समय बाद घोषित किए गए थे। 17 दिनों की अवधि (14 दिन की प्रारंभिक अवधि और डिलीवरी लेने के लिए 3 दिन की छूट) 26 अक्टूबर, 1952 को समाप्त हो गई, लेकिन अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि सफल बोलीदाताओं की ओर से भुगतान करने और डिलीवरी लेने के लिए समय



बढ़ाने के लिए एक सामान्य अनुरोध किया गया था और बोर्ड द्वारा एक परिपत्र जारी करके 10 नवंबर 1952 तक ऐसा विस्तार दिया गया था। हम पहले ही मान चुके हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा बोली को वापस लेने का कोई वैध तरीका नहीं था और उनकी जानकारी में बोर्ड ने 8 अक्टूबर, 1952 को ही उनके बयान वापस लेने को खारिज कर दिया था। अपीलकर्ताओं की बोर्ड द्वारा दिए गए विस्तार में रुचि थी, यह 22 अक्टूबर, 1952 के उनके टेलीग्राम से स्पष्ट हो जाता है। ए- 129) विस्तार की पुष्टि की मांग कर रहा है। 10 नवंबर, 1952 के बाद। पुन बिक्री की कुछ उचित सूचना जारी करनी होगी, इसलिए चूककर्ता कॉफी को नवम्बर, 1952 के महीने में आयोजित पूल नीलामी में बिक्री के लिए नहीं रखी जा सकती थी। अगली पूल नीलामी दिसंबर, 1952 में आयोजित की जानी थी और इसलिए, 18 दिसंबर, 1952 को पुनः बिक्री की सूचना जारी करने के बाद 23 दिसंबर, 1952 को पूल नीलामी आयोजित करके पुनः बिक्री आयोजित की गई थी। हमारे विचार में, दोनों न्यायालयों का यह विचार सही था कि उचित समय के भीतर पुनः बिक्री आयोजित की गई थी।

चूंकि अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा आग्रह की गई सभी दलीलें विफल हो गई हैं, इसलिए अपील को खर्च के साथ खारिज कर दिया जाता है।

पी.बी.आर

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री रमेश कुमार करोल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।